

पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार : डॉ. यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को इंदौर में एक निजी होटल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटलों और बड़ी परियोजनाओं में निवेश से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों का विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028 में ऊज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर का महत्व और बढ़ गया है। ऊज्जैन के निकट होने के कारण इंदौर में पर्यटकों, श्रद्धालुओं और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में व्यापारिक



आयोजनों, बैठकों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

डॉ. यादव ने कहा कि होटल पर्यटन, व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ शहर की आधुनिक

आतिथ्य सुविधाओं को भी मजबूत करेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, सुमित मिश्रा, श्रवण सिंह चावड़ा और मयंक राज सिंह भदौरिया उपस्थित थे।

लाइली बहनों को मिलेगी आज 41वीं किस्त की सौगात

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही ग्राम में आयोजित लाइली बहना योजना सम्मेलन में प्रदेश की पात्र महिलाओं को 41वीं किस्त की राशि अंतरित करेंगे।

सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये प्रति महिला के मान से राशि भेजी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री 144 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत करना है। योजना के तहत पात्र

सामान्य लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पंजीकृत पात्र महिलाओं को योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रतिमाह 900 रुपये की सहायता दी जाती है। राशि आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाती है। जून 2023 में योजना की पहली किस्त जारी की गई थी। सितंबर 2026 तक 40 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। अब 14 अक्टूबर को 41वीं किस्त जारी होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना में 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री 14,415.93 लाख रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन करेंगे।

शैक्षणिक पदों पर भर्ती शीघ्र करें, पीएम-उषा की राशि का समय पर उपयोग हो : परमार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उच्च शिक्षा मंत्री इंंदर सिंह परमार ने विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती शीघ्र पूरी करने और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत आवंटित राशि का निर्धारित समय-सीमा में उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डिजिटल मूल्यांकन की कार्ययोजना लागू करने और स्वीकृत विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करने पर भी जोर दिया।

श्री परमार की उपस्थिति में मंगलवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के 17 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बीच डिलीवरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और संस्थागत प्रगति का निर्धारित लक्ष्यों एवं सत्यापित उपलब्धियों



के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। समझौते के तहत सात प्रमुख क्षेत्रों में 46 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्वविद्यालयों का आकलन होगा। इनमें शैक्षणिक गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन, सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, शोध एवं नवाचार, वित्तीय प्रबंधन, रोजगारपरकता, विद्यार्थी कल्याण और सतत विकास शामिल हैं। शैक्षणिक कैलेंडर का समय पर पालन, परीक्षा परिणामों की घोषणा, ऑनलाइन विद्यार्थी

सेवाएं, शोध प्रकाशन, पेटेंट, अनुदान के उपयोग और रोजगार संबंधी गतिविधियों को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 को आधार वर्ष बनाया गया है। विश्वविद्यालयों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के लक्ष्यों की प्रगति का आकलन होगा। निर्धारित लक्ष्यों में कमी मिलने पर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

धूप की तलखी कुछ कम होगी बौछारें पड़ने के भी आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मानसून ने भले ही प्रदेश से विदा हो चुका है, लेकिन वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। जिसके चलते ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं। साथ ही हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं।

बादलों की मौजूदगी के चलते रात के तापमान में मामूली बढ़त हो सकती है। दिन के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में वातावरण शुष्क बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक प्रदेश में रात का सबसे कम 16.6 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर में दर्ज किया गया। मंगलवार को दिन का सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर में रिकार्ड हुआ। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग

में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में सक्रिय हुआ है। पूर्वी राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना है।

वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों में बनी इन मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से बुधवार-गुरुवार को प्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मौसम का मिजाज कुछ बदल सकता है। बादलों के छाने के कारण रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दिन का तापमान कुछ बढ़ सकता है। साथ ही ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। शेष इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रह सकता है।

किसान संघ का सरकार को अल्टीमेटम दशहरे तक समस्याएं सुलझाने की मांग



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली कटौती, खाद-बीज की कमी, सिंचाई के लिए पानी और फसलों की खरीदी से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार को दशहरे तक का अल्टीमेटम दिया है।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्री आंजना ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात 10:30 बजे बिजली काट दी जाती है। इससे किसानों के साथ बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को भी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती का मुद्दा कैबिनेट में भी उठ चुका है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए संपर्क करने के बावजूद जवाब नहीं मिला है।

संघ ने मांग की कि जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है, उनकी खरीदी उसी दर पर

हो। सोयाबीन और धान की खरीदी में भावांतर योजना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। आंजना ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में मंडियों का संचालन ठीक से नहीं हो रहा, जिससे किसानों को उजड़ बेचने में परेशानी होती है।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 20 से 22 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं और कुछ किसानों के पास सिंचाई के लिए केवल 10 से 15 दिन का पानी बचा है। संघ ने प्रभावित क्षेत्रों में कम पानी में तैयार होने वाली फसलों के बीज उपलब्ध कराने तथा खाद वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग की।

आंजना ने जमीन अधिग्रहण में किसानों के हितों का ध्यान रखने और उद्योगों के लिए पथरीली व कम उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता देने की बात भी कही। संघ ने चेतावनी दी कि दशहरे तक समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा।

शिक्षाकर्मियों को टीईटी से छूट पर 60 दिन में फैसला करे सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों वर्ग-2 और वर्ग-3 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने की मांग पर राज्य सरकार को 60 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।

अनिल कुमार तोमर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों तथा वर्ष 1997 से 1999 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की थी। उन्होंने पदोन्नति में भी टीईटी से राहत देने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि इस संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन पर निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के

► **हाईकोर्ट ने 2001 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों के लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए निर्देश**

► **हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों को टीईटी से छूट देने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया**

60 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी सभी लंबित आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार करें और स्पष्ट कारणों के साथ निर्णय लें। इसकी जानकारी संबंधित शिक्षाकर्मियों को भी दी जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों को टीईटी से छूट देने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने केवल लंबित आवेदनों पर निर्धारित समय में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया गया।

अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता अनुमान : मुख्यमंत्री

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2026 और 2027 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बढ़ती क्षमताओं और विस्तारित होती संभावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने इसे हर्ष और गर्व का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का प्रमाण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने से विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।



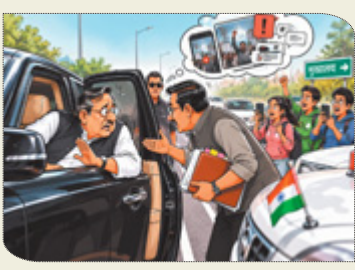
• कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना

लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पद पर रहने के बाद प्रमोशन पाकर ऊपर पहुंचे साहब अपने विभाग और अपने ऊपर आंच आने पर जवाब की जगह सिर्फ इतना ही कह पा रहे हैं कि निगाहें किसी पर हैं और निशाना कहीं और।



• मामला संभालने कोई और...

एक जिले में अचानक जेन अल्फा की सक्रियता बड़े साहब की परेशानी का कारण बन गई, क्योंकि साहब मुख्यालय पर थे ही नहीं। जैसे ही बड़े साहब को मीडिया से खबरें मिलीं कि मामला आपकी ओर बढ़ रहा है, साहब ने तुरंत छोटे साहब से रास्ते में ही मिलकर मामला संभाल लिया। साहब कहाँ गए थे और एक नंबर में या दो नंबर में, यह चर्चा का विषय है।



• गले की हड्डी...

पिछले दिनों एक विभाग में बड़े साहब ने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में सुपर से ऊपर वाले साहब की उपस्थिति में अपने बड़े साहब से शीर्ष नेतृत्व को असंभव को संभव करने की घोषणाएं तो करवा दीं, लेकिन अब उन्हें पूरा करना विभाग के लिए भारी पड़ रहा है।



• खर्चा तो ठीक, पर हिसाब कहाँ...

पिछले कुछ सप्ताह से मध्यप्रदेश भर में बड़ी-बड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं के आयोजनों की भरमार थी। आयोजन, कार्यक्रम और यात्राएं तो हो गईं, अब भुगतान का समय आया तो सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। सरकार के वित्त विभाग ने मितव्ययिता बरतने के लिए कुछ खर्चों और भुगतानों पर पहले से ही रोक लगा रखी है।



न्यू मार्केट में जीएसयू का प्रदर्शन...

भोपाल : राजधानी के न्यू मार्केट में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन (जीएसयू) के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने पीले झंडे और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मोके पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। छात्रों के हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित तख्तियां थीं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में एसएमई विशेषज्ञ की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि नए अभ्यर्थियों को अवसर देने के बजाय पद का कार्य विवरण ऐसे कर्मचारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो अक्टूबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाला है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भर्ती विज्ञापन में आवश्यक योग्यताओं के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर भी सवाल उठे हैं। यह पद सूचना प्रौद्योगिकी और उभरती तकनीकों से संबंधित है। ऐसे में तकनीकी योग्यता और आवश्यक शैक्षणिक मानदंड स्पष्ट करने की मांग की जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों

► एसएमई विशेषज्ञ पद के लिए शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट नहीं होने और सेवानिवृत्त कर्मचारी को अवसर देने के आरोप

को समान अवसर मिल सकें। निगम की पिछली भर्तियों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। दावा है कि पिछले दो वर्षों में संबंधित विभाग के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विज्ञापन जारी कर दोबारा काम पर रखा गया। इसके अलावा, निगम में संविदा पर कार्यरत करीब 150 कर्मचारी संविदा नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करने के साथ अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है।

प्रहलाद पटेल और राधा सिंह ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मंत्री राधा सिंह ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित



अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

